

इस्लामाबाद वार्ता फेल होने से ईरान नुकसान में नहीं है

ईरान का होर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण बरकरार रहेगा तथा अब वह अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रख सकेगा और निर्बाध रूप से इसे आगे बढ़ा सकेगा

-अंजन राय-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 12 अप्रैल। रविवार को अमेरिका-ईरान वार्ता अचानक बिना किसी समझौते के खत्म हो गई, जो कोई असामान्य बात नहीं थी। इसके उलट, अगर जल्दी कोई समाधान निकल आता तो वह ज्यादा हैरान करने वाला होता। असल में, पिछले पचास वर्षों से अमेरिका और ईरान के बीच चली आ रही कड़वी दुश्मनी पहली आमने-सामने की बैठक में खत्म होना आसान नहीं था। इतनी उच्च स्तर की बैठक से पहले जरूरी कूटनीतिक तैयारी भी पूरी तरह नहीं की गई थी। जल्दबाजी में हुई इस बैठक का असफल होना लगभग तय था।

इस बातचीत के असफल होने के बाद, अगर अमेरिका-इजरायल तुरंत फिर से हमला शुरू नहीं करते, तो ईरान को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। वह होर्मुज़ स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगा और वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क भी वसूल सकता है। साथ ही, वह

- वार्ता फेल होने का एक प्रमुख कारण यह था कि दोनों पार्टियाँ, अलग-अलग उम्मीदों, किसी हद तक विपरीत आशाओं के साथ, वार्ता करने आई थीं।
- अमेरिका फटाफट अंतरिम समाधान चाहता था, जिससे युद्ध को चुपचाप दफन किया जा सके। दूसरी ओर ईरान, एक बहुत बड़ी और भारी टीम के साथ आया था, विचारों का लंबा आदान-प्रदान और सौदेबाजी करके अपनी मांगों को मनवाने के लिए।
- एक मजे की बात यह भी है कि ईरान ने राष्ट्रपति ओबामा की सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय "एग््रीमेंट" किया था, न्यूक्लियर प्लांट्स के बारे में और जिसे ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद आनन-फानन में रद्द कर दिया। ट्रंप का यह कृत्य अब अमेरिका को भारी पड़ रहा है। एग््रीमेंट रद्द हो जाने के बाद अब ईरान पूर्णतया स्वतंत्र है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने के लिए। वो अब यूरेनियम का परिष्करण केवल 36 प्रतिशत ही करने को बाध्य नहीं है और उसपर यह शर्त भी लागू नहीं है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल पावर प्लांट्स चलाने तक सीमित रहे।

अपने परमाणु संयंत्रों को फिर से बना सकता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को बिना रुकावट जारी रख सकता है। दोनों पक्ष अलग-अलग उम्मीदों और रणनीतियों के साथ बातचीत में आए थे। अमेरिका जल्दी समाधान चाहता था, यानी किसी तरह का

अस्थायी समझौता, जिससे टकराव खत्म हो सके। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इस वार्ता को अविश्वास, शक और खराब भावना से भरा बताया। अमेरिका ने ईरान से ईमानदारी से बातचीत करने की अपील की थी।

ईरान एक बड़ी वार्ता टीम के साथ आया था और वह लंबी बातचीत तथा कड़ा मोलभाव करना चाहता था, ताकि उसकी मुख्य मांगों को मान्यता मिल सके। इनमें उसके परमाणु कार्यक्रम के अधिकार को अमेरिका द्वारा स्वीकार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका हमारा भरोसा नहीं जीत सका- ईरान

तेहरान/इस्लामाबाद, 12 अप्रैल। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आयोजित शांति वार्ता नाकाम होने के बाद दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान से अपने अपने देशों के लिए निकल चुके हैं। इस शांति वार्ता को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर बाघर गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट में जानकारीयां दी हैं। उन्होंने कहा है कि

- ईरान संसद के स्पीकर ने कहा कि अमेरिका ने हमारे तर्क समझ लिए, अब उसे तय करना है, हमारा भरोसा जीत सकता है या नहीं।

अमेरिका ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा है। उन्होंने लिखा बातचीत से पहले मैंने इस बात पर जोर दिया था कि हमारे पास जरूरी अच्छी नीयत और इच्छाशक्ति है, लेकिन पिछले दो युद्धों के अनुभवों की वजह से हमें दूसरी तरफ वाले पर कोई भरोसा नहीं है।

उन्होंने आगे लिखा ईरानी प्रतिनिधिमंडल में मेरे साथियों मिनाब168 ने आगे की सोच वाली पहल की, लेकिन दूसरी तरफ वाला आखिरकार इस बातचीत के दौर में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह ब्लॉक करेगा अमेरिका?

अगर ईरान के जहाज भी स्ट्रेट से बाहर नहीं आ पाएंगे तो, ईरान भी अपना तेल बेच नहीं पाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत विफल होने के बाद होर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का वादा किया है। यह एक दोधारी तलवार है, जो अंत में ईरान को झुका सकती है। लेकिन यह डॉनल्ड ट्रंप की हार को भी दिखाता है। स्पष्ट है कि अमेरिका की बड़ी सैन्य ताकत के बावजूद ट्रंप होर्मुज़ स्ट्रेट को खोल पाने में सक्षम नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग है, जिससे दुनिया का लगभग पाँचवाँ हिस्सा तेल गुजरता है। इस स्ट्रेट के तट पर ईरानी सेना इतनी मजबूत स्थिति में है कि अमेरिकी नौसेना और बड़े जहाज भी इस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।

ईरान ने होर्मुज़ को चुनिंदा तरीके से बंद कर रखा है, जिससे अमेरिका के सहयोगी देश अपने जहाज इस रास्ते से नहीं भेज पा रहे हैं। ईरान की इस नीति, कभी रोकना और कभी जाने देना, की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अचूकपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इससे ईरान को बड़ा फायदा हो रहा है। वह दूसरों को अपने तेल को होर्मुज़

- अमेरिका के पास, इस्लामाबाद में वार्ता फेल होने के बाद अब केवल यह ही एक विकल्प बचा, ईरान को घुटनों पर लाने के लिए।
- इस ब्लॉकड से ईरान की दूसरी आमदनी, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का उपयोग करने वाले जहाजों से दो मिलियन डॉलर प्रति जहाज "टोल" वसूल करने की योजना भी खटाई में पड़ जाती है।
- कुछ जानकार तो अब यह तक कह रहे हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह ब्लॉक करने का प्लान अमेरिका पहले ही काम में ले लेता, तो बिना युद्ध करे ईरान को "समर्पण" की स्थिति में ला सकता था।

के रास्ते ले जाने नहीं दे रहा है। इसके अलावा, ईरान उन जहाजों से भारी शुल्क भी वसूल रहा है, जो इस रास्ते से गुजरते हैं, प्रति जहाज 20 लाख डॉलर से भी अधिक।

अगर इस स्ट्रेट को पूरी तरह बंद कर दिया जाए और ईरानी जहाजों को भी गुजरने न दिया जाए, तो यह ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। वह अपना तेल बेच नहीं पाएगा और न ही जहाजों से शुल्क वसूल पाएगा। अगर अमेरिका ने ईरान के साथ सीधा युद्ध करने के बजाय, पहले ही

होर्मुज़ को बंद कर दिया होता, तो इतने महंगा युद्ध और मानव जीवन की भारी हानि से बचा जा सकता था। इसका असर अमेरिका के एक और विरोधी देश पर भी पड़ेगा। चीन अपनी बड़ी तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक ईरान पर निर्भर है। अगर होर्मुज़ बंद हो जाता है, तो ईरान के बाद सबसे ज्यादा नुकसान चीन को होगा। यह बीजिंग में होने वाले डॉनल्ड ट्रंप और शी जिन्पिंग के प्रस्तावित शिखर सम्मेलन से पहले एक बड़ा मुद्दा बन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुतिन ने ईरान-अमेरिका शांति वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश की

ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर वार्ता में पुतिन ने मध्य पूर्व के शांति समझौतों में सहयोग का ऑफर दिया

मॉस्को, 12 अप्रैल। पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका की वार्ता बेनतीजा होने की घोषणा के बाद रूस ने मध्यस्थ बनने की इच्छा जताई है। खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकयन से फोन पर बात की और ये ऑफर दिया।

इंटरफैक्स समाचार एजेंसी ने बताया कि पुतिन ने कहा कि रूस मध्य पूर्व में शांति समझौते में सहयोग जारी रखने के लिए तैयार है। क्रेमलिन ने दोनों नेताओं की बातचीत का विवरण देते हुए बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संघर्ष के राजनीतिक और राजनयिक समाधान को खोज में और अधिक सहयोग देने तथा मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों में मध्यस्थता करने की अपनी तत्परता पर जोर दिया।

सवाल ये है कि ईरान अगर राजी भी हो जाता है तो क्या अमेरिका इसके लिए मानेगा? हालांकि, इसमें बहुत

- यह माना जा रहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध में अमेरिका को मध्यस्थ लिया गया था, अतः अब अमेरिका को रूस के प्रस्ताव को नकारना मुश्किल होगा।

ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है कि रूस ने यूक्रेन के मसले में अमेरिका को मध्यस्थ मान लिया है और अमेरिका के जरिए ही रूस-यूक्रेन के बीच बात हो रही है। ये भी हो सकता है कि पुतिन ने

ये ऑफर या तो ईरान के आग्रह पर दिया होगा या इसमें अमेरिका की भी रजामंदी होगी। हालांकि, कुछ दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि अमेरिका-ईरान पुतिन के ऑफर को स्वीकार करते हैं या नहीं।

भाजपा ने शिवराज सिंह को बिहार में पर्यवेक्षक बनाया

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए सरगमियां तेज हो गई हैं। रविवार को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने

बिहार में पार्टी विधायक दल के नए नेता के चयन के लिए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पर्यवेक्षक बनाया है। उनकी मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी, जहाँ नए नेता के नाम पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने लोकसभा-राज्यसभा में व्हिप जारी किया

नई दिल्ली, 12 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी विशेष संसद सत्र को लेकर अपने सभी सांसदों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों के लिए तीन लाइन का व्हिप

- महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर विशेष संसद सत्र में 16 से 18 अप्रैल तक सभी सांसदों व मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।

जारी करते हुए 16 से 18 अप्रैल तक सदन में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा है। पार्टी की ओर से स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इस अवधि के दौरान किसी भी सांसद या केन्द्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं दी जाएगी। सभी सदस्यों को लगातार (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन

आज दोपहर 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका दाह संस्कार किया जाएगा



से कोल्हापुर और फिर मुंबई चला गया। परिवार का भरपूर-पोषण करने के लिए उन्होंने और उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर ने फिल्मों में गाना और अभिनय करना शुरू कर दिया था। आशा भोसले का एक और गुण था, खाना पकाना। एक बार एक समाचार पत्र को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि अगर उनका गायन करियर सफल नहीं होता तो क्या होता, तो उन्होंने कहा था, "मैं बावर्ची बन जाती। मैं चार घरों में खाना बनाकर पैसे

कमा लेती।" उन्होंने दुर्बई, कुवैत, आबू धाबी, दोहा, बहरीन और काहिरा में रेस्तरां खोला था। रेस्तरां की इस श्रृंखला की देखरेख काफी गुप करता है। आशा भोसले ने आठ दशकों में 12 हजार से अधिक गीत गाये और तीन पीढ़ीयों की नायिकाओं को उन्होंने अपनी आवाज दी। उन्हें अपने शानदार करियर में अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले जिनमें प्रमुख 9 फिल्मफेयर अवॉर्ड्स (7 सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका सहित), दो

- आठ दशक के संगीत-जीवन में आशा ने 12 हजार से अधिक गीत गाये और तीन पीढ़ियों की नायिकाओं को अपनी आवाज दी। उन्होंने 9 फिल्म फेयर अवार्ड, दो राष्ट्रीय पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में पद्म विभूषण शामिल है। 2001 में उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। वर्ष 2011 में संगीत इतिहास में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

होर्मुज़ पर टोल देने वाले जहाजों को रोकेंगे- ट्रंप

वॉशिंगटन, 12 अप्रैल। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में हुई नाकाम शांति वार्ता के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त और तीखा बयान जारी किया है, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि

- शांति वार्ता विफल होने के बाद ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी।

ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य खोलने का वादा किया था, लेकिन जानबूझकर उसे तोड़ा, जिससे दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता, डर और संकट की स्थिति पैदा हो गई है। उनके मुताबिक, यह कदम अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए गंभीर खतरा बन चुका है और ईरान की गैर-जिम्मेदार हरकतों ने वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की नौसेना होर्मुज़ जलडमरूमध्य में आने-जाने वाले सभी जहाजों की निगरानी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- जाल खं बाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 12 अप्रैल। कोलकाता की सामाजिक शब्दावली में एक विशेष समूह का लंबे समय से खास स्थान है- 'भद्रलोक', जिसे अक्सर 'मध्याविति' (मध्य वर्ग) कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा के संवाद में, इस सामाजिक वर्ग को कभी मिडिलिंग क्लास कहा गया, और बाद में यह शिक्षित मध्यमवर्ग के रूप में विकसित हुआ, जिसे कभी-कभी बस मिडिल क्लास कहा जाता है। औपनिवेशिक काल में, ब्रिटिश

- यह मनःस्थिति, शहरी कोलकातावासी की एस.आई.आर. के बारे में राय में भी प्रतिबिंबित हो रही है।
- पंद्रह साल के लगातार शासन के बाद ममता बनर्जी सरकार के प्रति कुछ निराशा होना तो स्वाभाविक भी है, तथा सरकार के भ्रष्टाचार के कई स्कैम भी सामने आए हैं।
- आर.जी. कर हॉस्पिटल काण्ड व संदेशखाली की घटनाओं से यह भावना भी फैली है कि ममता सरकार बंगाली संस्कृति की शालीनता को खत्म करती जा रही है। इस पतन को रोकने के लिए एस.आई.आर. प्रक्रिया का पूरा होना, वोट बैंक की राजनीति को तोड़ने के लिए जरूरी है।

अधिकारी, जो सबसे पहले इस सामाजिक समूह के सम्पर्क में आये, उन्होंने उन्हें शिक्षित देशी कहा। हालांकि, अधिकांश आधुनिक सामाजिक वर्गों

की तरह, भद्रलोक समुदाय की सीमाओं को सटीक रूप से परिभाषित करना कठिन है। पश्चिम बंगाल, और विशेष रूप से

कोलकाता में, भद्रलोक ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक राय को आकार देने में केन्द्रीय भूमिका निभाता रहा है। पिछले दशकों में, कांग्रेस पार्टी को

कोलकाता के शहरी मध्यमवर्ग में पर्याप्त समर्थन प्राप्त था, जबकि ग्रामीण बंगाल का झुकाव अधिकतर वामपंथी दलों की ओर था। बाद में, वाम सरकार

के अंतिम चरण में, बुद्धदेव भट्टाचार्य को शहरी शिक्षित मतदाताओं में महत्वपूर्ण समर्थन मिला, जबकि ममता बनर्जी ग्रामीण बंगाल में राजनीतिक पसंद बनकर उभरीं। अंततः, बनर्जी ने दोनों वर्गों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। लेकिन 2026 के विधानसभा चुनाव में शहरी कोलकाता के कुछ हिस्सों में अलग पैटर्न उभर रहा है। कुछ क्षेत्रों में, बनर्जी की लगभग पंद्रह साल की सरकार के बाद, उसका स्पष्ट विरोध दिखाई दे रहा है। भद्रलोक समुदाय के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से

जम्मू, 12 अप्रैल। दक्षिण कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की वार्षिक तीर्थयात्रा 3 जुलाई को शुरू होगी और 57 दिनों के बाद 28 अगस्त को समाप्त होगी। 13 से 70 वर्ष की आयु के तीर्थयात्री यात्रा कर सकते हैं और पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में श्री अमरनाथ जी प्राइड

- तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा।

बोर्ड (एसएसबी) की बैठक में यात्रा की तारीखें तय की गईं। उपराज्यपाल ने कहा कि इस साल की तीर्थयात्रा थोड़ी लंबी होगी, जो लगभग 57 दिनों तक चलेगी। तीर्थयात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और 15 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित की गई है। सिन्हा ने कहा कि पहली पूजा 19 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)